

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1134 / 2015 / जयपुर
2. अपील संख्या – 1135 / 2015 / जयपुर
3. अपील संख्या – 1136 / 2015 / जयपुर
4. अपील संख्या – 1137 / 2015 / जयपुर
5. अपील संख्या – 1138 / 2015 / जयपुर
6. अपील संख्या – 1139 / 2015 / जयपुर
7. अपील संख्या – 1140 / 2015 / जयपुर
8. अपील संख्या – 1141 / 2015 / जयपुर
9. अपील संख्या – 1142 / 2015 / जयपुर

मैसर्स मंगल इलेक्ट्रीकल इण्डो प्रा० लि०,  
सी-61ए, रोड नं० 1-सी,  
वी.के.आई.ए., जयपुर  
बनाम

.....अपीलार्थी

सहायक आयुक्त,  
प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य  
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जी.एन.शर्मा, अभिभाषक  
श्री रामकरण सिंह,  
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 22/06/2018

निर्णय

1. उपर्युक्त नौ अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें अपीलार्थी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 26 एवं 61 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "सीएसटी एक्ट" कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत पारित आदेशों दिनांक 18.02.2013/28.02.2013 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज की पुष्टि करने को विवादित किया गया है। अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

लगातार.....2

अपील सं.	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	वित्तीय वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
1134/15	01/अपी.ІІІ/आरवैट/ई/जयपुर	2007-08	31,549	20,193	63098
1135/15	02/अपी.ІІІ/सीएसटी/ई/जयपुर	2007-08 (CST)	124	80	248
1136/15	03/अपी.ІІІ/ आरवैट/ई/जयपुर	2008-09	39,576	20,582	79152
1137/15	04/अपी.ІІІ/ सीएसटी/ई/जयपुर	2008-09 (CST)	14,496	4,532	28992
1138/15	05/अपी.ІІІ/ आरवैट/ई/जयपुर	2009-10	2,29,983	91,993	459966
1139/15	06/अपी.ІІІ/ सीएसटी/ई/जयपुर	2009-10 (CST)	17,290	6,916	34580
1140/15	07/अपी.ІІІ/ आरवैट/ई/जयपुर	2010-11	2,97,045	83,175	594090
1141/15	08/अपी.ІІІ/ सीएसटी/ई/जयपुर	2010-11 (CST)	1,24,727	34,922	249454
1142/15	09/अपी.ІІІ/ आरवैट/ई/जयपुर	2011-12	13,877	2,219	27754

- समस्त प्रकरणों के तथ्य समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जावे।
- प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 22.05.2012 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट-तृतीय, जोन-प्रथम जयपुर द्वारा किया गया। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा ट्रांसफॉर्मर्स (Transformers) का विनिर्माण किया जाता है जिसकी राज्य के भीतर व राज्य के बाहर स्थित विभिन्न विद्युत कम्पनियों को सप्लाई की जाती है। लेखा पुस्तकों की जांच पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा अपने क्रय इन्वॉइसेज में जो फ्रेट व इन्श्योरेंस चार्ज वसूल किये गये हैं उन पर वैट/सीएसटी संग्रहीत नहीं किया गया। अपीलार्थी को विभिन्न विद्युत कम्पनियों एवं व्यवहारियों से जो कार्यादेश प्राप्त हुए हैं उनमें F.O.R. Destination पर माल सप्लाई करने का प्रावधान है। कार्यादेश की शर्तों के अवलोकन करने पर जांच अधिकारी ने पाया कि क्रेता की साईट पर माल पहुंचाने तक माल का स्वामित्व अपीलार्थी का है तथा गंतव्य पर माल पहुंचाने का समस्त जोखिम भी अपीलार्थी का है। वैट इन्वॉइसेज के अवलोकन से पाया गया कि विक्रय राशि पर वैट/सीएसटी चार्ज किये जाने के पश्चात उसमें फ्रेट व इन्श्योरेंस चार्ज को जोड़ा गया है जिसे टैक्सेबल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रकरण नियमानुसार सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरण किये जाने पर सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत कार्यवाही करते हुए उपरोक्त तालिकानुसार कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा इन्हें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखा गया तथा शास्ति को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर ये अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

१

३१

लगातार.....3

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रारम्भ करते हुए अभिवाक किया कि अपीलार्थी कम्पनी ने निविदा प्रपत्र एवं सप्लाई अनुबन्ध की शर्तों के तहत माल की सप्लाई की है। अपीलार्थी ने अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार फ्रेट एवं इन्श्योरेंस को पृथकशः अंकित करते हुए माल की सप्लाई का अनुबन्ध किया जिसमें निविदा व अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी ने माल की सप्लाई अलग दर से की है तथा अन्य दरों के अनुसार डिलीवरी, फ्रेट, इन्श्योरेंस चार्ज को क्रेता फर्म से प्राप्त किया है जो कर योग्य बिक्री के भाग नहीं है, इसलिये इन राशियों पर कोई कर वसूल नहीं किया है। अधिनियम की धारा 2(36) के एक्सप्लेनेशन-III के अनुसार उक्त खर्चे बिक्री मूल्य में शामिल नहीं किये गये हैं क्योंकि अपीलार्थी ने इनको सप्लाई शर्तों में पृथकशः दिखाया है इसलिये इन राशियों को क्रेता के लिये (on behalf of the buyer) प्राप्त करने के कारण बिलों में करयोग्य आवर्त में घोषित नहीं किया है।
5. अपीलार्थी का यह भी कथन है कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखने में विधिक भूल कारित की गई है। अतः उन्होंने कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त भी उद्धरित किये :-
- i) विनोद कोल सिन्डीकेट बनाम आयुक्त बिक्री कर, उ.प्र. (1988) 73 एसटीसी 317 (SC) निर्णय दिनांक 30.10.87
  - ii) सीटीओ बनाम मैसर्स आगरा ब्रेवरीज कॉरपोरेशन; (2002) 11 सेल्स टैक्स टूडे 138 (RTB)
  - iii) मैसर्स आई.डी.एल. एक्सपलोसिब्ल बनाम एसीटीओ; अपील संख्या 777/2014/उदयपुर, निर्णय दिनांक 17.04.2015 (RTB)
6. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फ्रेट व इन्श्योरेंस चार्जेज को बिक्री मूल्य का भाग मानते हुए जो करारोपण किया है वह विधिसम्मत है, अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने तथा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरणों में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या विक्रय बिलों में भाड़ा राशि एवं बीमा चार्ज के रूप में पृथक से वसूल की गई राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस पर कर आरोपणीय है अथवा नहीं ? इस सन्दर्भ में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 2(36) एवं इसके Explanation III तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 2(h) का अवलोकन किया जाना भी समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

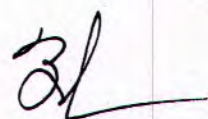
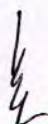
**RVAT Act: Section 2(36) "sale price"** means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

**"Explanation III :-** Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice.

**CST Act: Sec. 2(h) "sale price"** means the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods, less any sum allowed as cash discount according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof other than the cost of freight or delivery or the cost of installation in cases where such cost is separately charged.

उक्त परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि माल की सुपुर्दगी के समय अथवा उससे पूर्व किये गये किसी कृत्य के लिए प्रभारित की गई राशि 'विक्रय मूल्य' का भाग मानी जायेगी। यद्यपि फ्रेट एवं ट्रान्सपोर्टेशन के सम्बन्ध में किये गये अन्य व्यय जो कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार क्रेता के लिए विक्रेता

लगातार.....5



व्यवहारी द्वारा किए गये हों (for or on behalf of the buyer), वे विक्रय मूल्य का भाग नहीं होंगे। इससे स्पष्ट है कि यदि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उक्त खर्च माल के समग्र मूल्य का हिस्सा हैं तो ऐसी दशा में इसे विक्रय मूल्य का भाग माना जायेगा।

8. विक्रय मूल्य की परिभाषा का अवलोकन करने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा की गई माल की राज्य के भीतर आपूर्ति के संबन्ध में निष्पादित अनुबंधों में माल की कीमत संबंधी शर्तों/उपबन्धों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रतिदर्श के तौर पर अपीलार्थी द्वारा राज्य की विभिन्न विद्युत आपूर्ति कम्पनियों के साथ किये गये अनुबंधों के सुसंगत अंश निम्नानुसार हैं :-

- (1) मैसर्स अजमेर विद्युत वितरण कम्पनी लि० के साथ किये गये अनुबन्ध के

मुख्य अंश

**"2. PRICES, TAXES AND DUTIES**

**A) PRICES**

The unit F.O.R. destination price mentioned above at clause No. 1 "Schedule of Material and Prices" is inclusive of excise duty & CESS thereon, sales tax/VAT, packing forwarding loading, freight and insurance charges for delivery of transformers at our stores any where in the Jurisdiction of AVVNL in Rajasthan by Road transport. The prices of transformer & protection unit with box are variable as per IEEMA price variation formula appended herewith without any ceiling with Base Date 01/11/2007.

**E) FREIGHT AND INSURANCE CHARGES :**

The unit F.O.R. destination price mentioned in Clause No. 1 includes Freight & Insurance charges at the fixed rate of Rs. 100.00 (Rs One Hundred only) for delivery each transformer with protection unit at our stores anywhere in the Jurisdiction of AVVNL in Rajasthan by Road Transport. If the delivery of transformers is obtained from supplier's works by the consignee the aforesaid fixed F&I charges shall be deducted from the contract price."

- (2) मै. जोधपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि० के साथ किये गये अनुबन्ध के  
मुख्य अंश

**" BREAK-UP OF F.O.R. UNIT PRICE**

**Transformers**

Ex works price	:	Rs.	32536.71
E.D. @ 14% & Cess on ED @ 3%	:	Rs.	4691.79
VAT	:	Rs.	1489.14
Freight	:	Rs	300.00
Insurance	:	Rs.	INCL
FOR Unit Destination Price	:	Rs.	<b>39017.64</b>
<b>Meter &amp; Protection Box with MCCB</b>			
Ex works price	:	Rs.	3025.29
E.D. @ 14% & Cess on ED @ 3%	:	Rs.	436.25
VAT	:	Rs.	138.46
F&I	:	Rs	Incl
FOR Unit Destination Price	:	Rs.	<b>3600.00</b>

लगातार.....6

!

31

## 2. PRICES, TAXES & DUTIES

**A) PRICES :** The prices as mentioned above are all adjusted FOR destination price inclusive of packing and forwarding charges, excise duty, VAT, freight and insurance. The prices of 11/0.433 KV distribution transformers of 25 KVA are variable as per IEEMA formula mentioned in the governing specification. If material is delivered beyond delivery schedule, the benefit of PV Clause will be regulated as per original schedule of delivery or actual delivery as may be advantageous to the Nigam, considering base date as on 1.1.02008. The prices of LV bushing cover cum metering box with MCCB is FIRM."

- (3) मै. जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि० के साथ किये गये अनुबन्ध के मुख्य अंश :

### "2. PRICES, TAXES AND DUTIES

#### A) PRICES

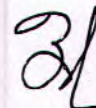
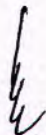
The unit F.O.R. destination price mentioned above at clause No. 1 is inclusive of excise duty, Sales tax/vat, packing, forwarding, freight and insurance charges, loading at firm's works and unloading of material at store/site for delivery of transformers at our stores any where in the State of Rajasthan by Road transport. The prices of transformer is further variable as per IEEMA price variation formula appended herewith without any ceiling with Base Date as 01/02/2008. The price of Meter Protection Box is FIRM.

#### E) FREIGHT AND INSURANCE CHARGES :

The unit F.O.R. destination price mentioned in Clause No. 1 includes Freight & Insurance charges at the fixed rate of Rs. 195.00 Per Transformer with Meter Protection Box, loading at firm's works unloading of material as store / site for delivery of transformers at our stores anywhere in the State of Rajasthan by Road Transport.

If the delivery of transformers is obtained from supplier's works by the consignee the aforesaid fixed F&I charges shall be deducted from the contract price."

9. इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में किये गये विक्रय के सम्बन्ध में क्रयादेशों की शर्तों का अवलोकन करना भी आवश्यक है, जिनमें Freight के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं। प्रतिदर्श के तौर पर अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर की विभिन्न विद्युत आपूर्ति कम्पनियों के साथ किये गये अनुबन्धों के सुसंगत अंश निम्नानुसार हैं :-



लगातार.....7

(1) मै. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ (उ.प्र.)

"6. Packing forwarding, freight and insurance for transportation and 30 days storage thereafter for supply of material F.O.R. Destination anywhere in U.P. has been covered by a supplementary order, which is being issued separately."

(2) एम.पी. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)

"2. Accepted Prices :- The accepted prices indicated in Schedule-I are in Rupees FOR Destination and VARIABLE as per IEEMA Price variation formula with basic prices ruling as on 01.02.11."

(3) मध्य गुजरात वीज़ कम्पनी लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात)

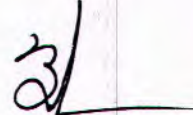
"2. Railway Receipt (R.R.) / Truck Receipt (T.R.):

All goods should be dispatched freight paid and the R.R. / T.R. should be forwarded directly to the consignee by registered letter and not through any Bank or MGVCL'S Office at Vadodara. In case of local suppliers, the R.R. / T.R. should be forwarded to the consignees directly and in both the cases it should be immediately intimated on dispatch of the stores, as otherwise demurrage charges if any paid by the consignee will be deducted from your bills. It is essential that packing notes and prices invoices should be furnished to the consignees in respect of every consignment with a copy to this office.

A clear R.R. / T.R. should be obtained from the Railway Authorities / Transport, Authorities without any ambiguity, otherwise the supplier will be held responsible for any damages / shortage claim rejected by the Authorities for want of a clear R.R. / T.R. **Materials may be dispatched by any convenient mode of transport and up to MGVCL's stores i.e. F.O.R. Destination"**

(4) एम.वी.वी.एन.एल, लखनऊ (उ.प्र.)

"Packing forwarding, average freight and insurance for transportation and 30 days storage thereafter for supply of material F.O.R. destination any wherein M.V.V.N.L. has been covered by a supplementary order which is being issued separately."



10. उक्त अनुबन्धों के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रेताओं द्वारा जारी क्रय आदेशों में जो क्रय मूल्य उल्लेखित किये गये हैं, वे F.O.R. destination prices हैं जिनमें माल भाड़ा तथा बीमा के खर्चे भी शामिल हैं।
11. प्रश्नगत बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना सुसंगत होगा जिनमें माल भाड़ा एवं बीमा आदि को बिक्री मूल्य का भाग माना गया है। इस संबंध में सर्वप्रथम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि० बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (1978) 4 SCC 271 के प्रकरण में दिया गया निर्णय उल्लेखनीय है जिसमें राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में दी गई 'बिक्री मूल्य' तथा 'करयोग्य टर्नओवर' की परिभाषाओं की विवेचना करते हुए यह निर्णीत किया गया है कि अनुबन्ध की शर्तों में माल के समग्र बिक्री मूल्य में माल भाड़ा शामिल होने की दशा में इसे विक्रय मूल्य तथा करयोग्य टर्नओवर का भाग माना जायेगा। उक्त निर्णय के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं :-

*"Though we are concerned in these appeals with assessments made under both Rajasthan Sales Tax Act, 1954 and Central Sales Tax Act, 1956, it would be sufficient to refer only to the provisions of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954, since the material provisions of both the Acts are identical. Section 3 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 provides that every dealer whose turnover in the previous year exceeds a certain limit shall be liable to pay tax on his taxable turn over, subject to the provisions of that Act. "Taxable turnover" is defined in section 2(s) to mean that part of the "turnover" which remain after deducting the aggregate amount of proceeds of certain categories of sales and "turnover", according to section 2(t), means "the aggregate of the amount of sale prices received or receivable by a dealer in respect of the sale or supply of goods-". The definition of 'sale price' is given in section 2(p) and according to that definition, it means:*

*".....the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods, less any sum allowed as cash discount according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof other than the cost of freight or delivery or the cost of installation in case where such cost is separately charged".*

लगातार.....9



*"This definition is in two parts. The first part says that 'sale price' means the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods. Here, the concept of real price or actual price retainable by the dealer is irrelevant. The test is, what is the consideration passing from the purchaser to the dealer for the sale of the goods. It is immaterial to enquire as to how the amount of consideration is made up. whether it includes excise duty or sales tax or freight, the only relevant question to ask is as to what is the amount payable by the purchaser to the dealer as consideration for the sale and not as to what is the net consideration retainable by the dealer."*

*"We may then take a case where a dealer transports goods from his factory to his place of business and sells them at a price which is arrived at after taking into account 'freight and handling charges' incurred by him in transporting the goods. The amount of 'freight and handling charges' included in the price would obviously be the part of the 'sale price', because it would be payable by the purchaser to the dealer as part of the consideration for the sale of the goods. The same would be the legal position even if the 'freight and handling charges' are shown separately in the bill and added to the price of the goods, for the character of the payment would remain the same. Since 'freight and handling charges' represent expenditure incurred by the dealer in making the goods available to the purchaser at the place of sale, they would constitute an addition to the cost of the goods to the dealer and would clearly be a component of the price charged to the purchaser. The amount of 'freight and handling charges' would be payable by the purchaser not under any statutory or other liability 'out as part of the consideration for the sale of the goods and it would, therefore, form part of 'sale price' within the meaning of the first part of the definition."*

*"We may now take another example which is very much near to the one which we have already discussed. The dealer may, instead of transporting the goods from his factory or his place of business and selling them there, enter into a contract of sale F.O.R.. destination railway station. Where such a contract is made, the seller undertakes an obligation to put the goods on rail and arrange to have them carried to the destination railway station at his expense. The delivery of the goods to the purchaser in such a case is complete at the destination railway- station and till then the risk continues to remain with the dealer. The freight is payable by the dealer since he has to arrange for the goods to*



*be carried by rail to the destination railway station at his expense and there is no obligation on the purchaser to pay the freight The purchaser is concerned only to pay the agreed price for the delivery of the goods at the destination railway station. The agreed price being inclusive of the freight, it would be a matter of indifference to the purchaser as to what is the amount of freight. Even if there is any fluctuation in the amount of freight, since the making of the contract, the purchaser would have no concern, because he is liable to pay only the agreed price which includes the freight, whatever it be. The dealer may, in such a case, pay the freight and charge the agreed price to the purchaser, or he may obtain a railway receipt on the basis of freight to pay" and request the purchaser to pay the freight at the time of taking delivery of the goods from the railway at the destination railway station and give the purchaser credit for the amount of the freight against the agreed price. The latter would merely be a convenient mode of paying the agreed price. Since it is the obligation of the dealer to deliver the goods free on rail destination railway station, the dealer is liable to pay the freight s between him and the purchaser and the purchaser can very well refuse to accept the railway receipt which is not "freight pre-paid" but "freight to pay". But he may, ordinarily as a reasonable businessman he would, accept such railway receipt and pay the amount of freight on behalf of the dealer. When the purchasers pay the amount of freight in such a case, it would be; as part of the agreed price and not as freight vis-a-vis the dealer. The amount of freight paid by the purchaser and shown in the bill as deducted from the agreed price would, therefore, clearly form part of "sale price" and fall within the first part of the definition."*

इस प्रकार उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विक्रय मूल्य का अनुबंध माल की डिलीवरी क्रेता तक पहुंचाने तक होने की स्थिति में सम्पूर्ण राशि विक्रय राशि की परिभाषा के प्रथम भाग अनुसार अर्थात् Amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods के तहत मानी जायेगी एवं ऐसे मामलों में फ्रेट की राशि को पृथक से दर्शाने की स्थिति में भी इसे टर्नओवर और विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता है।

12. उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में विक्रय मूल्य में फ्रेट की राशि को सम्मिलित करते हुए अनुबंध किया

1/2

3/

लगातार.....11

गया है, उनमें विक्रय मूल्य की परिभाषा अनुसार पूरी तय राशि विक्रय मूल्य का भाग होगा एवं जिन मामलों में केवल माल की कीमत ही दर्शाई जाती है एवं माल की डिलीवरी ट्रांसपोर्टर को देने तक ही विक्रेता का दायित्व हो एवं उसके आगे की रिस्क क्रेता की होती है वहां फ्रेट की राशि पर कर आरोपित नहीं किया जा सकता। इसी तरह उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बिलों में फ्रेट की राशि को अलग दर्शाने मात्र से उस राशि को विक्रय मूल्य से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सम्पूर्ण राशि विक्रय मूल्य के रूप में लिया जाना निश्चित किया गया है।

13. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **India Meters Ltd. Vs State of Tamilnadu (2010) 9 SCC 423 (SC)** के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 07-08-2010 में भी भाड़े की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस पर आरोपित कर को उचित ठहराया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण के तथ्य इन प्रश्नगत अपीलों के तथ्यों के समान ही थे जहां M/s India Meters Ltd. द्वारा विभिन्न राज्यों के Electricity Boards को इलेक्ट्रिक मीटर आपूर्ति किये गये थे तथा जहां आपूर्ति की शर्तों में माल की आपूर्ति F.O.R. destination किये जाने के प्रावधान थे। उक्त निर्णय के कुछ मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं :-

*"14. In the instant case, the obligation to pay the freight was clearly on the appellant as there was no sale at all, unless the goods were delivered at the premises of the buyer and in order to so deliver, the assessee necessarily had to incur freight charges.*

*15. The transfer of title to the goods as provided in Clause 10 read with Clause 6 of the agreement was to be at the place of delivery in the premises of the buyer. Though the contract mentioned the price of the electric meters as ex-factory price, the delivery was not at the factory gate. The specification of what the price would be at the factory gate, therefore, does not in the context of the term subject to which the sale was agreed to be effected, render it the point or the location at which the sale can be said to have been completed. Had the sale been completed at the factory gate, the expenses incurred thereafter by way of freight charges would then be capable of being regarded as expenditure which was in the nature of a post-sale expenditure and, if paid by the seller, regarded as an amount paid by such seller on behalf of the buyer.*

4

31

**20.** *When the transfer of the property or the goods is to be at the place of the buyer to which the seller is under an obligation to transport the goods, the expenditure incurred by the seller on freight in order to carry the goods from his place of manufacture to the place at which he is required under the contract to deliver, would thus become part of the amount for which the goods are sold by the seller to the buyer and would fall within the scope of "turnover".*

**41.** *When we apply the ratio of the judgments of the English Courts and of our Courts, the conclusion becomes obvious that the amount of freight and insurance charges incurred by the dealer forms part of the sale price.*

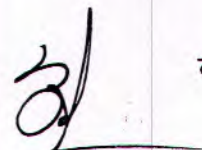
**42.** *We may reiterate that in this case, there was specific contract entered into by and between the parties and according to the relevant clause of the contract, the ownership of the goods will remain with the supplier till they are delivered at the destination station.*

**43.** *In view of the clear clause of the contract, no other view is possible. In our considered view, the High Court was totally justified in affirming the judgment of the Tribunal. No interference is called for. These appeals being devoid of any merit are dismissed with costs."*

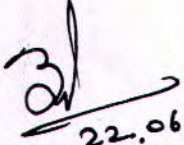
14. इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय/अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा कई अन्य प्रकरणों में भी माल भाड़े को बिक्री मूल्य का भाग होना निर्णीत किया है। उक्त निर्णय निम्नलिखित हैं:-


- i) Cement Marketing Co. of India Ltd. Vs Assistant Commissioner of Sales Tax, Indore (1980) 1 SCC 71
- ii) Cement Marketing Co. of India Ltd. Vs Commissioner of Commercial Taxes, Karnataka (1980) Supp. SCC 373
- iii) TVL Ramco Cement Distribution Co. Pvt. Ltd. Vs State of Tamil Nadu (1993) 1 SCC 192
- iv) Bihar State Electricity Board and Anr. v. Usha Martin Industries and Anr. (1997) 5 SCC 289
- v) State of A.P. v. A.P. Paper Mills Ltd. (2005) 1 SCC 719
- vi) Black Diamond Beverages and Anr. v. Commercial Tax Officer, Central Section, Assessment Wing, Calcutta and Ors. (1998) 1 SCC 458
- vii) Greaves Chitram Limited V/s State of Tamil Nadu (2003) 133 STC 364 (Mad.)

15. व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य इन हस्तगत प्रकरणों से भिन्न हैं क्योंकि प्रस्तुत प्रकरणों में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार माल की डिलीवरी F.O.R. Destination पर दिया जाना, माल की Delivery तक Transit Risk विक्रेता की होना एवं माल का स्वामित्व ट्रांसपोर्टेशन के बाद हस्तान्तरण होने के तथ्य स्पष्ट हैं।



16. प्रस्तुत प्रकरणों के तथ्यों से यह निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को क्रेता विद्युत कम्पनियों को F.O.R. Destination पर माल की डिलीवरी देनी थी एवं माल की डिलीवरी तक ट्रांज़िट रिस्क विक्रेता की ही थी। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं संविदा की शर्तों तथा ऊपर वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में माल की F.O.R. Destination Delivery होने तथा माल की मार्गस्थ जोखिम अपीलार्थी की होने के कारण Freight and Insurance राशि को विक्रय मूल्य का भाग माना जाना पूर्णतः न्यायोचित एवं विधिसम्मत है, अतः इस संबंध में अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य हैं।
17. परिणामतः अपीलीय आदेशों की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।
18. निर्णय सुनाया गया।

  
22.06.2015  
(ओमकार सिंह आशिया)  
सदस्य

  
(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य